

[2020] 3 एससीआर 1015

अरुण कुमार गुप्ता

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

(2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 190)

27 फरवरी, 2020

[एल. नागेश्वर राव और दीपक गुप्ता, जे.जे.]

सेवा कानून:

अनिवार्य सेवानिवृत्ति - न्यायिक अधिकारियों की - सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में चुनौती दी गई - सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, उच्च न्यायालय की अनुवीक्षण समिति ने अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए पहले की कार्रवाई को मंजूरी दी - उच्च न्यायालय की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित अनुवीक्षण समिति का संकल्प - आयोजित: एक अधिकारी के संबंध में जिसके खिलाफ शिकायतें थीं कि सिविल सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान, अपने व्याख्यानों में उन्होंने अत्यधिक कामुक भाषा का इस्तेमाल किया था और उन्होंने गर्म लोहे के साथ एक धोबी को चोट पहुंचाई थी - दो उदाहरण उनके खिलाफ मामले का फैसला करने के लिए पर्याप्त हैं - दूसरे अधिकारी के संबंध में, उनकी प्रतिष्ठा और अखंडता पर एक से अधिक अवसरों पर संदेह किया गया है, कानून और प्रक्रिया के बारे में उनका ज्ञान औसत पाया गया था, बार के सदस्यों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं थे - सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रतिकूल प्रविष्टियां किसी भी स्तर पर अपना स्टिंग नहीं खोती हैं - न्यायिक अधिकारी की सत्यनिष्ठा उच्च कोटि की होनी चाहिए, यहां तक कि एक भी विपथन की अनुमति नहीं है - उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो जांच और स्थायी समितियों के सदस्य थे, ने दो अवसरों पर सुविचारित और सुविचारित निर्णय लिए हैं - उच्चतम न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी

शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि दुर्भावना या ऐसे तथ्य हैं जो इतने स्पष्ट हैं कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति - प्रभाव और इसके विचार के लिए मानदंड - चर्चा की गई।

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा:

आयोजित: 1. अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विषय पर कानून, विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों के मामले में, संक्षेप में इस प्रकार किया जा सकता है: (i) न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्देश देने वाला आदेश प्रकृति में दंडात्मक नहीं है; (ii) एक आदेश जिसमें [एक न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई नागरिक परिणाम नहीं है; (iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए न्यायिक अधिकारी के मामले पर विचार करते समय न्यायिक अधिकारी के संपूर्ण अभिलेख पर विचार किया जाना चाहिए, हालांकि बाद वाले और अधिक समकालीन अभिलेख को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए; (iv) पदोन्नतियों का अर्थ यह नहीं है कि न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्णय करते समय पूर्व के प्रतिकूल रिकार्ड की जांच नहीं की जा सकती है; (v) वॉश ऑफ सिद्धांत न्यायिक अधिकारियों के मामले में विशेष रूप से सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में लागू नहीं होता है; (vi) न्यायालयों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति सामान्यतः उच्च न्यायालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (समितियों) की सिफारिश पर निदेशित होती है, अत्यधिक सावधानी और संयम के साथ न्यायिक पुनवलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। [अनुच्छेद 16] [1031-बी-ई]

भारत संघ बनाम कर्नल जेएन सिन्हा (1970) 2 एससीसी 458: [1971] 1 एससीआर 791; गुजरात राज्य बनाम सूर्यकांत चुनीलाल शाह (1999) 1 एससीसी 529: [1998] 3 सप्ल. एससीआर 293; बैकुंठ नाथ दास बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (1992) 2 एससीसी 299: [1992] 1 एससीआर 836; चंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2003) 6 एससीसी 545: [2003] 1 सप्ल. एससीआर 674; सैयद टी.ए. नक्शबंदी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (2003) 9 एससीसी 592: [2003] 1 सप्ल. एससीआर 114, प्यारे

मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य (2010) 10 एससीसी 693: [2010] 11 एससीआर 216; राजेंद्र सिंह वर्मा बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर (एनसीटी दिल्ली) (2011) 10 एससीसी 1: [2011] 12 एससीआर 496; आर.सी. चंदेल बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (2012) 8 एससीसी 58: [2012] 7 एससीआर 205; राजस्थान एसआरटीसी बनाम बाबू लाल जांगिड़ (2013) 10 एससीसी 551: [2013] 11 एससीआर 159; पटना उच्च न्यायालय बनाम श्याम देव सिंह (2014) 4 एससीसी 773: [2014] 4 एससीआर 541 ; डी. रामास्वामी बनाम तमिल नाडु राज्य (1982) 1 एससीसी 510: [1982] 3 एससीआर 75 - पर भरोसा किया।

2.1 जहां तक 2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 190 में याचिकाकर्ता का संबंध है, उसके खिलाफ दो बहुत गंभीर आरोप हैं। पहला यह कि जब वह रांची में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के उप निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, तो 10 महिलाओं, जो सिविल सेवा परिवीक्षाधीन थीं, ने आरोप लगाया कि वह अपने व्याख्यान के दौरान अनुचित और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग कर रहे थे, अभद्र उदाहरणों का हवाला देते हुए और दोहरे अर्थ वाले शब्दों का उपयोग कर रहे थे। जिससे महिला अधिकारियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शिकायतों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने व्याख्यान के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अत्यधिक कामुक थी। [अनुच्छेद 18] [1031-एच; 1032- ए-बी]

2.2. एक और आरोप यह भी है कि उसने धोबी के सिर पर गर्म लोहा रखकर एक धोबी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई थी, जिसने कथित तौर पर अपने कपड़े ठीक से इस्त्री नहीं किए थे। प्रधान जिला न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि पीड़ित ने घटना के तुरंत बाद व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क किया था और उन्होंने (प्रधान जिला न्यायाधीश) पाया कि पीड़ित को जलने की चोटें आई थीं और उन्होंने पीड़ित का इलाज कराया। यह सच है कि याचिकाकर्ता को उत्तराधिकारी न्यायिक अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था जिसके समक्ष शिकायतकर्ता ने इनकार कर दिया था। यह सच है कि याचिकाकर्ता को उत्तराधिकारी न्यायिक अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था, जिसके समक्ष शिकायतकर्ता ने किसी भी चोट से इनकार किया था, लेकिन उत्तराधिकारी प्रधान जिला न्यायाधीश ने अपने पूर्ववर्ती प्रधान जिला न्यायाधीश की जांच करने की भी परवाह नहीं की, जिनसे न केवल धोबी द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया था, बल्कि जिन्होंने खुद

जलने की चोटों को गौर किया था और पीड़ित का इलाज कराया था। इसलिए, जांच समिति सही थी कि पीड़ित पर अपनी शिकायत वापस लेने के लिए कुछ दबाव डाला गया होगा। [अनुच्छेद 19] [1032-सी-ई]

2.3 उपरोक्त दो उदाहरण याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले का फैसला करने के लिए पर्याप्त हैं। जहां तक इस दलील का संबंध है कि अनुवीक्षण समिति ने केवल 1992- 1993 से 2004-2005 तक प्रविष्टियां ली थीं और 2005-2006 से 2016-2017 तक प्रविष्टियों को नजरअंदाज कर दिया था, उच्च न्यायालय के वकील द्वारा यह समझाया गया है कि सभी ए सी आरएस अनुवीक्षण समिति के समक्ष थे, लेकिन आदेश में यह केवल प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं जिन्हें गौर किया गया है। यहां तक कि अगर इन प्रतिकूल प्रविष्टियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता को उपरोक्त कारणों से राहत नहीं दी जा सकती है। [अनुच्छेद 20] [1032-एफ-जी]

3. जहां तक 2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 391 में याचिकाकर्ता का संबंध है, कई मामलों में उसका अभिलेख बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वर्ष 1996-1997, 1997-1998 और 2004-2005 में उनकी प्रतिष्ठा और ईमानदारी पर एक से अधिक बार संदेह किया गया है। उन्हें कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां दी गई हैं। वर्ष 2015-2016 में, यहां तक कि कानून और प्रक्रिया के बारे में उनका ज्ञान औसत पाया गया और बार के सदस्यों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं पाए गए। उनके खिलाफ अवैध परितोषण के लिए जमानत देने के भी आरोप हैं और न्यायिक आयुक्त, रांची (जो प्रधान जिला न्यायाधीश के समकक्ष हैं) की प्रतिवेदन में इस आरोप में सार पाया गया है। याचिकाकर्ता ने आदेश में यह उल्लेख करते हुए जमानत दी थी कि दंड संहिता, 1860 की धारा 327 जमानती है, जबकि अपराध गैर-जमानती है और न्यायिक अधिकारी की अखंडता के बारे में एक अलिखित चेतावनी 2012 में उसे जारी की गई थी। [अनुच्छेद 21] [1032-एच; 1033-ए सी]

4. सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रतिकूल प्रविष्टियां किसी भी स्तर पर अपना डंक नहीं खोती हैं। एक न्यायिक अधिकारी की सत्यनिष्ठा उच्च कोटि की होनी चाहिए और यहां तक कि एक भी विपथन की अनुमति नहीं है। [अनुच्छेद 22] [1033-सी डी]

¹ (1970) 2 एस सी सी 458

5. वर्तमान मामलों में, इस मामले पर अनुवीक्षण समिति द्वारा दो अवसरों पर विचार किया गया है और अनुवीक्षण समिति की सिफारिशों को स्थायी समिति द्वारा दोनों अवसरों पर स्वीकार किया गया है। की गई कार्रवाई किसी एक अधिकारी या न्यायाधीश द्वारा नहीं की गई है, यह सामूहिक निर्णय है, पहले जांच समिति द्वारा और तत्पश्चात् स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों, जो छानबीन समिति और स्थायी समिति के सदस्य थे, सुविचारित निर्णय लिया है। जब तक *दुर्भावना* के आरोप नहीं लगते हैं यह तथ्य इतने स्पष्ट नहीं होते हैं कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय समर्थन योग्य नहीं है, तब तक यह अदालत न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी। ऐसे मामलों में न्यायिक पक्ष की अदालत को ऐसे सामूहिक निकायों के फैसले को रद्द करने से पहले संयम बरतना चाहिए जिसमें उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं। [अनुच्छेद 22 और 23] [1033-डी-एफ]

केस लॉ संदर्भ

[1971] 1 SCR 791	पर निर्भर	अनुच्छेद 5
[1998] 3 सप्ला SCR 293	पर निर्भर	अनुच्छेद 5
[1992] 1 SCR 836	पर निर्भर	अनुच्छेद 6
[2003] 1 सप्ला SCR 674	पर निर्भर	अनुच्छेद 7
[2003]1 सप्ला SCR 114	पर निर्भर	अनुच्छेद 8
[2010] 11 SCR 216	पर निर्भर	अनुच्छेद 9
[2011] 12 SCR 496	पर निर्भर	अनुच्छेद 10
[2012] 7 SCR 205	पर निर्भर	अनुच्छेद 11
[2013] 11 SCR 159	पर निर्भर	अनुच्छेद 12
[2014] 4 SCR 541	पर निर्भर	अनुच्छेद 13

[1982] 3 SCR 75

पर निर्भर अनुच्छेद 14

सिविल मूल क्षेत्राधिकार पर निर्भर है: 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 190

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

के साथ।

2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 391

याचिकाकर्ता के लिए अलख आलोक श्रीवास्तव, रंजन कुमार राय, एसएस जौहर, संकल्प तिवारी, नीलेश तिवारी, अमित कुमार, एडवोकेट हैं।

सुनील कुमार, अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ एडवोकेट, हिमांशु शेखर, जमनेश कुमार, पार्थ शेखर, चंद्र भूषण प्रसाद, सुश्री सुकृति भारद्वाज, उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय

दीपक गुप्ता, जे. द्वारा दिया गया था।

1. ये रिट याचिकाएं दो तत्कालीन न्यायिक अधिकारियों द्वारा दायर की गई हैं जो झारखंड राज्य में न्यायिक सेवा के सदस्य थे और उन आदेशों के विरुद्ध निर्देशित हैं जिनके द्वारा उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है। दो रिट याचिकाओं के संबंध में, जो इस निर्णय का विषय हैं, इस न्यायालय ने 06.09.2018 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"रिट याचिका संख्या 190/2018 और 391/2018 लंबित रहेगी। झारखंड उच्च न्यायालय उन सामग्रियों की संपूर्णता के आलोक में मामले पर पुनर्विचार करना चाहेगा जो झारखंड उच्च न्यायालय के महा रजिस्ट्रार और उच्च न्यायालय के विद्वान वकील द्वारा सुनवाई में हमारे समक्ष रखी गई हैं।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय इस मामले को तय करने के लिए स्वतंत्र है जैसा कि उचित माना जा सकता है और हमारे पास इस स्तर के योग्यता पर कोई राय

¹ (1970) 2 एस सी सी 458

व्यक्त नहीं की। झारखंड उच्च न्यायालय पर्याप्त कारणों के साथ वर्तमान आदेश के संदर्भ में अपने निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस आदेश का निर्णय आज से दो महीने के अंत में हमारे सामने रखा जाए।

दो महीने बाद मामलों की सूची बनाएं।“

उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, मामलों को झारखंड उच्च न्यायालय की अनुवीक्षण समिति के समक्ष रखा गया और अनुवीक्षण समिति ने 11.10.2018 को फिर से पर्याप्त कारण पाए और इन अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए की गई पूर्व कार्रवाई को मंजूरी दी। अनुवीक्षण समिति के प्रस्ताव को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थायी समिति के समक्ष रखा गया, जिसने 25.10.2018 को अनुवीक्षण समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

2. इन दोनों रिट याचिकाओं में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेशों और विशेष रूप से अनुवीक्षण समिति द्वारा बताए गए कारणों या अनदेखी की गई सामग्री को चुनौती दी गई है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश झारखंड सेवा संहिता, 2001 के नियम 74 (बी) (ii) के संदर्भ में पारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार है:

"(ii) संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने की पूर्व सूचना देने के बाद, या इस तरह के सूचना के बदले तीन महीने के वेतन और भत्ते के बराबर राशि दे सकता है, लोक हित में उससे अपेक्षा करता है कि वह उस तारीख को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाए जिस तारीख को ऐसा सरकारी सेवक तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करता है या पचास वर्ष की आयु प्राप्त करता है या उसके बाद सूचना में विनिदष्ट की जाने वाली किसी तारीख को सेवानिवृत्त होता है।

पूर्वोक्त नियम मौलिक नियमों के नियम 56 (जे) के *समवर्ती* है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए मुख्य तर्क यह हैं कि उनकी सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित में नहीं है: उनके पूरे सेवा अभिलेख विशेष रूप से समकालीन अभिलेख को ध्यान में नहीं रखा गया है और यह भी कि याचिकाकर्ताओं को विभिन्न पदोन्नति दी गई है जो उनकी पिछली प्रतिकूल प्रविष्टियों को धोने का प्रभाव डालेंगे, यदि कोई हो।

4. वर्तमान मामले का निर्णय करते समय हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हम न्यायिक अधिकारियों के मामलों से निपट रहे हैं। न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षित सत्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा का मानक अन्य अधिकारियों से अपेक्षित बहुत अधिक है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए हम पहले इस विषय पर कानून पर चर्चा करेंगे और फिर इन दोनों मामलों को गुण-दोष के आधार पर लेंगे।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

5. इस न्यायालय ने **भारत संघ बनाम कर्नल जे एन सिन्हा**¹ में कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति में नागरिक परिणाम शामिल नहीं हैं। यह इस मुद्दे से भी निपटता है कि सार्वजनिक हित क्या है। निम्नलिखित टिप्पणियां उचित हैं:

"9. अब मौलिक नियम 56 (जे) के व्यक्त शब्दों पर आते हुए यह कहता है कि उपयुक्त प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है यदि उसकी राय है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। उस शक्ति का प्रयोग नियम में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है, जिनमें से एक यह है कि संबंधित प्राधिकारी की राय होनी चाहिए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। यदि वह प्राधिकरण सदाशयी रूप से उस राय को बनाता है, तो उस राय की शुद्धता को अदालतों के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह एक पीड़ित पक्ष के लिए यह तर्क देने के लिए खुला है कि अपेक्षित राय नहीं बनाई गई है या निर्णय संपार्श्विक आधार पर आधारित है या यह एक मनमाना निर्णय है। पहले प्रतिवादी ने सरकार द्वारा बनाई गई राय को दुर्भावना के आधार पर चुनौती दी।

¹ (1970) 2 एस सी सी 458

लेकिन वह मैदान विफल हो गया है। उच्च न्यायालय ने उस याचिका को स्वीकार नहीं किया। हमारे सामने इस पर जोर नहीं दिया गया। आक्षेपित आदेश के आधार पर हमला नहीं किया गया था कि आवश्यक राय नहीं बनाई गई थी या यह कि बनाई गई राय मनमानी थी। पहले प्रतिवादी की सेवा की शर्तों में से एक यह है कि सरकार पचास वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी समय उसे सेवानिवृत्त करने का विकल्प चुन सकती है यदि उसे लगता है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के कारण वह सेवानिवृत्ति से पहले अर्जित किसी भी अधिकार को नहीं खोता है। **अनिवार्य सेवानिवृत्ति में कोई नागरिक परिणाम शामिल नहीं है। उपर्युक्त नियम 56 (जे) सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अभिप्रेत नहीं है। यह नियम केवल संविधान के अनुच्छेद 310 में सन्निहित आनंद सिद्धांत के पहलुओं में से एक का प्रतीक है।** नियम के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते समय उपर्युक्त प्राधिकारी के साथ विभिन्न विचारों पर विचार किया जा सकता है। कुछ मामलों में, सरकार यह महसूस कर सकती है कि एक विशेष पद को सार्वजनिक हित में अधिक उपयोगी रूप से एक अधिकारी द्वारा धारण किया जा सकता है जो धारण करने वाले की तुलना में अधिक सक्षम है। यह हो सकता है कि पद धारण करने वाला अधिकारी अक्षम न हो लेकिन उपर्युक्त प्राधिकारी अधिक कुशल अधिकारी को पसंद कर सकता है। यह भी हो सकता है कि कुछ प्रमुख पदों पर जनहित में यह आवश्यक हो सकता है कि निस्संदेह क्षमता और अखंडता वाले व्यक्ति को वहां होना चाहिए। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सभी संगठनों में और विशेष रूप से सरकारी संगठनों में, मृत लकड़ी का अच्छा सौदा है। इसे काटना जनहित में है। मौलिक नियम 56 (जे) व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी के अधिकारों और जनता के हितों के बीच संतुलन रखता है। जबकि सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम सेवा की गारंटी दी जाती है, सरकार को अपनी मशीनरी को सक्रिय बनाने और उन लोगों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करके इसे और अधिक कुशल बनाने की शक्ति दी जाती है, जो उसकी राय में सार्वजनिक हित में नहीं होने चाहिए।

11. हमारी राय में उच्च न्यायालय ने यह सोचने में गलती की कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति में नागरिक परिणाम शामिल हैं। ऐसी सेवानिवृत्ति से सरकारी कर्मचारी को उसकी पिछली सेवा के कारण प्राप्त कोई भी अधिकार नहीं छीना जाता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि सभी या सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग की सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष निर्धारित की जाती है, तो इसमें सिविल परिणाम शामिल होंगे। मौजूदा प्रणाली के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की कोई समान आयु नहीं है। सेवानिवृत्ति की आयु न केवल सरकारी कर्मचारी के हित के आधार पर बल्कि समाज की आवश्यकताओं के आधार पर भी तय की जाती है।

(महत्व सन्निविष्ट)

इस फैसले का गुजरात राज्य बनाम सूर्यकांत चुनीलाल शाह² में पालन किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने जनहित की अवधारणा पर बहुत विस्तार से विचार किया था।

6. बैकुंठ नाथ दास बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी³ में तीन न्यायाधीशों की पीठ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं:

"34. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत उभरकर सामने आते हैं:

(i) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सजा नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई कलंक नहीं है और न ही दुर्व्यवहार का कोई सुझाव है।

(ii) सरकार द्वारा यह राय बनाने पर आदेश पारित किया जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना जनहित में है। आदेश सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाता है।

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। जबकि उच्च न्यायालय या यह न्यायालय अपीलीय अदालत के रूप में मामले की जांच नहीं करेगा, वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि आदेश पारित किया गया है (ए) दुर्भावनापूर्ण या (बी) कि यह बिना किसी सबूत पर आधारित है या (सी) यह मनमाना है -

² (1999) 2 एस सी सी 529

³ (1992) 2 एस सी सी 299

इस अर्थ में कि कोई भी उचित व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बनाएगा; संक्षेप में, यदि यह एक विकृत क्रम पाया जाता है।

(iv) सरकार (या समीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो) को इस मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे अभिलेख पर विचार करना होगा - निश्चित रूप से संलग्न को इस मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे अभिलेख पर विचार करना होगा - निश्चित रूप से बाद के वर्षों के दौरान अभिलेख और प्रदर्शन को अधिक महत्व देना। इस प्रकार विचार किए जाने वाले रिकार्ड में स्वाभाविक रूप से गोपनीय अभिलेख/चरित्र नामावली में प्रविष्टियां शामिल होंगी, दोनों अनुकूल और प्रतिकूल। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसी टिप्पणियां अपना डंक खो देती हैं, खासकर तब, जब पदोन्नति योग्यता (चयन) पर आधारित हो, न कि वरिष्ठता पर।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर रद्द किए जाने योग्य नहीं है कि इसे पारित करते समय असंसूचित प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था। वह परिस्थिति अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती। हस्तक्षेप केवल ऊपर (iii) में उल्लिखित आधारों पर अनुमेय है। इस पहलू पर ऊपर अनुच्छेद 30 से 32 में चर्चा की गई है।

7. **चन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य⁴**, हालांकि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आवेदक कानून के अनुरूप नहीं था, इसने याचिकाकर्ता को इस आधार पर राहत नहीं दी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत भी, उच्च न्यायालय किसी भी समय किसी भी न्यायिक अधिकारी के प्रदर्शन का आकलन कर सकता है ताकि काली भेड़ को अनुशासित किया जा सके या मृत लकड़ी को बाहर निकाला जा सके। इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय की यह संवैधानिक शक्ति किसी भी नियम द्वारा सीमित नहीं है। संदर्भनिर्णय के अनुच्छेद 40 और 47 का संदर्भ दिया जा सकता है:

"40. भारत के संविधान का अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय को किसी भी समय किसी भी न्यायिक अधिकारी के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है ताकि काली भेड़ को अनुशासित किया जा सके या डेडवुड को बाहर निकाला जा

⁴ (2003) 6 एस सी सी 545

सके। उच्च न्यायालय की इस संवैधानिक शक्ति को किसी नियम या आदेश द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है।

Xxx

xxx

xxx

47. वर्तमान मामले में, हम उच्च न्यायिक अधिकारियों से निपट रहे हैं। हम तीन न्यायाधीशों की समिति द्वारा की गई टिप्पणियों पर पहले ही गौर कर चुके हैं। न्यायिक सेवा की प्रकृति ऐसी है कि यह संदिग्ध निष्ठा वाले व्यक्तियों की सेवा में निरंतरता का सामना नहीं कर सकती है या जिन्होंने अपनी उपयोगिता खो दी है।

8. *सैयद टी ए नक्शबंदी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य*⁵ के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालयों को उच्च न्यायालय की समिति/पूर्ण न्यायालय के लिए खुद को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित अवलोकन प्रासंगिक हैं:

"10... न तो उच्च न्यायालय और न ही यह न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी भी दर पर संबंधित उच्च न्यायालय की समिति/पूर्ण न्यायालय के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित कर सकता है या नहीं करेगा, उसी का स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन करने के लिए, जैसे कि अपील पर बैठा हो। दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा हमारे संज्ञान में लाई गई संपूर्ण सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम संतुष्ट हैं कि समिति/पूर्ण न्यायालय द्वारा अपनी सर्वसम्मत राय बनाने वाला मूल्यांकन न तो इतना मनमाना या मनमाना है और न ही इसे इतना तर्कहीन कहा जा सकता है कि किसी हस्तक्षेप को उचित ठहराने या उचित ठहराने के लिए न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दे। इस तरह के मूल्यांकन, मूल्यांकन और राय के निर्माण के मामलों में, कई कारकों की एक विशाल श्रृंखला एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और किसी भी कारक को किसी मुद्दे को हल करने या हल करने के लिए या दावों की मांग करने के लिए अनुपात से अधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चीजों की प्रकृति में यह मुश्किल होगा, पूर्ण न्यायालय द्वारा किए

⁵(2003) 9 एस सी सी 592

गए इस तरह के अभ्यास को न्यायिक समीक्षा के अधीन करना लगभग असंभव होगा, सिवाय एक असाधारण मामले को छोड़कर जब न्यायालय आश्वस्त है कि कुछ राक्षसी चीज जो नहीं होनी चाहिए थी, वास्तव में हुई है और केवल इसलिए नहीं कि कोई अन्य संभावित दृष्टिकोण हो सकता है या किसी को समिति/पूर्ण न्यायालय द्वारा किए गए अभ्यास के बारे में कुछ शिकायत है ...

9. *प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य*⁶ के मामले में न्यायिक अधिकारियों के एक मामले से निपटते हुए, इस न्यायालय ने उसी नियम के अधीन शक्तियों के संबंध में, कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, इस बिंदु पर कानून को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

"18. इस प्रकार, इस बिंदु पर कानून को इस आशय से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश एक सजा नहीं है और यह तब तक कलंक नहीं लगाता है जब तक कि इस तरह के आदेश को साबित कदाचार के लिए सजा देने के लिए पारित नहीं किया जाता है, जैसा कि वैधानिक नियमों में निर्धारित है। [देखें सुरेंद्र कुमार बनाम भारत संघ] [(2010) 1 एससीसी 158]। प्राधिकरण को संबंधित अधिकारी की प्रविष्टियों के समग्र प्रभाव पर विचार और जांच करनी चाहिए न कि एक अलग प्रविष्टि की, क्योंकि यह कुछ मामलों में अच्छी तरह से हो सकता है कि संतोषजनक प्रदर्शन के बावजूद, प्राधिकरण सार्वजनिक हित में एक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की इच्छा कर सकता है, क्योंकि उक्त प्राधिकरण की राय में, पद को एक अधिक कुशल और गतिशील व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाना चाहिए और यदि पर्याप्त सामग्री है यह दिखाने के लिए अभिलेख कि कर्मचारी ने "खुद को संस्था के प्रति दायित्व प्रदान किया", अदालत के लिए न्यायिक समीक्षा की अपनी सीमित शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है।"

10. *राजेंद्र सिंह वर्मा बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर (दिल्ली के एनसीटी)*⁷ में, यह न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा से एक न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति से निपट रहा था। यह माना गया कि यदि प्राधिकरण सदाशयी यह राय बनाता है कि किसी विशेष अधिकारी की ईमानदारी संदिग्ध है और ऐसे न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य रूप से

⁶(2010) 10 एस सी सी 693

⁷(2011) 10 एस सी सी 1

सेवानिवृत्त करना सार्वजनिक हित में है, तो ऐसे आदेश की न्यायिक समीक्षा बहुत सावधानी के साथ की जानी चाहिए। यह विशेष रूप से देखा गया था कि जब अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी को संबंधित अधिकारी के पूरे सेवा अभिलेख को ध्यान में रखना होगा। जिसमें गैर-संप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियां भी शामिल हो सकती हैं। यह इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा:

"218. संपूर्ण सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, यह माना जाना चाहिए कि समिति/पूर्ण न्यायालय द्वारा किया गया मूल्यांकन, उनकी सर्वसम्मत राय बनाते हुए, न तो इतना मनमाना है और न ही मनमौजी है और न ही इसे इतना तर्कहीन कहा जा सकता है, ताकि इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दिया जा सके या किसी हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सके। इस तरह के मूल्यांकन, मूल्यांकन और राय के निर्माण के मामलों में, कई कारकों की एक विशाल श्रृंखला एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और किसी भी कारक को किसी मुद्दे को हल करने या विचार करने या दावा करने की मांग करने के लिए अनुपात से बाहर उड़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चीजों की प्रकृति में, यह मुश्किल होगा, एक असाधारण मामले को छोड़कर जब न्यायालय आश्वस्त है कि कुछ वास्तविक अन्याय, जो नहीं होना चाहिए था, वास्तव में हुआ है और केवल इसलिए नहीं कि समिति/पूर्ण न्यायालय द्वारा किए गए अभ्यास के बारे में कोई अन्य संभावित दृष्टिकोण हो सकता है या किसी को कुछ शिकायत है।

219. इस प्रकार देखा गया, और अभिलेख पर तथ्यात्मक विवरण और सामग्री की पृष्ठभूमि में विचार किया गया, इस न्यायालय के लिए आक्षेपित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता या औचित्य नहीं है। इसलिए, तीन अपीलें विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।"

11. *आर.सी. चंदेल बनाम उच्च न्यायालय म. प्र.*⁸ में, इस न्यायालय ने इस विषय पर पूरे कानून से निपटने के बाद, कानून के निम्नलिखित 3 प्रश्न तैयार किए:

"18. विचारणीय प्रश्न इस प्रकार हैं:

⁸(2012) 8 एस सी सी 58

- (1) क्या अपीलार्थी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सरकार को सर्वसम्मत राय के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश और सरकार द्वारा जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में कोई कानूनी दोष है?
- (2) क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश इतना मनमाना या तर्कहीन है जो न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप को उचित ठहराता है?
- (3) क्या अपीलकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखने वाली खंड पीठ का दृष्टिकोण भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता को गलत मानता है?

न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलकर्ता को जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत और पुष्टि की गई थी और उसे चयन ग्रेड और उत्कृष्ट समय मान आदि भी दिया गया था, लेकिन यह माना गया कि ये पदोन्नति पहले की प्रतिकूल प्रविष्टियों को नहीं धोएंगी जो अभिलेख पर रहेंगी। निर्णय के अनुच्छेदग्राफ 26 और 29 का संदर्भ लेना उचित होगा जो इस प्रकार है:

"26. यह सच है कि अपीलकर्ता को 1985 में जिला न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की गई थी; उन्हें 24-3-1989 से कम चयन ग्रेड मिला; उन्हें मई, 1999 में सुपर टाइमस्केल से सम्मानित किया गया था और उन्हें 2002 में सुपर टाइमस्केल से ऊपर भी दिया गया था, लेकिन जिला न्यायाधीश के रूप में पुष्टि और चयन ग्रेड और सुपर टाइमस्केल प्रदान करने से पहले की प्रतिकूल प्रविष्टियां समाप्त नहीं होती हैं जो अभिलेख पर बनी हुई हैं और क्षेत्र में बनी हुई हैं। वेतनवृद्धि या उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति या अनुदान का मानदंड न्यायिक प्रणाली में न्यायिक अधिकारी की निरंतर उपयोगिता का आकलन करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया से भिन्न है। प्रणाली में एक न्यायिक अधिकारी की निरंतर उपयोगी सेवा के लिए क्षमता का आकलन करने में, उच्च न्यायालय को संपूर्ण सेवा अभिलेख को ध्यान में रखना आवश्यक है। एक न्यायिक अधिकारी का समग्र प्रोफाइल मार्गदर्शक कारक है। संदिग्ध ईमानदारी, संदिग्ध प्रतिष्ठा और उपयोगिता में

कमी वाले लोग सेवा या आयु की अपेक्षित लंबाई प्राप्त करने के बाद सेवा के लाभ के हकदार नहीं हैं।

XXX

XXX

XXX

29. न्यायिक सेवा कोई साधारण सरकारी सेवा नहीं है और न्यायाधीश इस तरह के कर्मचारी नहीं हैं। न्यायाधीश सार्वजनिक पद धारण करते हैं; उनका कार्य राज्य के आवश्यक कार्यों में से एक है। अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में, न्यायाधीश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यायाधीश जिस पद पर आसीन होता है वह लोक विश्वास का पद होता है। एक न्यायाधीश को त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा और अभेद्य स्वतंत्रता वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसे उच्च नैतिक मूल्यों के साथ मूल रूप से ईमानदार होना चाहिए। जब कोई वादी अदालत कक्ष में प्रवेश करता है, तो उसे सुरक्षित महसूस करना चाहिए कि जिस न्यायाधीश के समक्ष उसका मामला आया है, वह विश्वास करेगा जब कोई वादी अदालत कक्ष में प्रवेश करता है, तो उसे यह महसूस करना चाहिए कि जिस न्यायाधीश के समक्ष उसका मामला आया है, वह निष्पक्ष रूप से और किसी भी विचार से प्रभावित हुए बिना न्याय देगा। एक न्यायाधीश से अपेक्षित आचरण का मानक एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक है। यह कोई बहाना नहीं है कि चूंकि समाज में मानकों में गिरावट आई है, इसलिए समाज से लिए गए न्यायाधीशों से उच्च मानकों और नैतिक दृढ़ता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक न्यायाधीश, सीज़र की पत्नी की तरह, संदेह से परे होना चाहिए। न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता उन न्यायाधीशों पर निर्भर करती है जो इसे संचालित करते हैं। लोकतंत्र को फलने-फूलने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए न्याय प्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करना होगा और प्रत्येक न्यायाधीश को अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन ईमानदारी, निष्पक्षता और बौद्धिक ईमानदारी के साथ करना चाहिए।

12. राजस्थान एस आर टी सी बनाम बाबू लाल जांगीर⁹, इस न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया:

⁹(2013) 10 एस सी सी 551

"23. कानून का सिद्धांत जो स्पष्ट है और प्यारे मोहन लाल बनाम भारत संघ के फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है। झारखंड राज्य यह है कि किसी कर्मचारी की पदोन्नति के बाद उससे पहले की प्रतिकूल प्रविष्टियों की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी और जब सरकारी कर्मचारी के मामले में आगे पदोन्नति के लिए विचार किया जाना हो तो इसे मिटा दिया जा सकता है। हालांकि, इस "धोए गए सिद्धांत" का कोई आवेदन नहीं होगा जब किसी कर्मचारी के मामले का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है कि क्या वह सेवा में बनाए रखने के लिए फिट है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की आवश्यकता है। दिया गया तर्क यह है कि चूंकि ऐसा मूल्यांकन "संपूर्ण सेवा अभिलेख" पर आधारित है, इसलिए पहले की पुरानी प्रतिकूल प्रविष्टियों या पुरानी अवधि के अभिलेख पर विचार नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम यह जोड़ना जल्दबाजी कर सकते हैं कि जबकि इस तरह के अभिलेख को ध्यान में रखा जा सकता है, साथ ही, तत्काल पिछली अवधि के सेवा अभिलेख को उचित विश्वसनीयता और महत्व देना होगा। उदाहरण के लिए, कुछ बहुत पुरानी प्रतिकूल प्रविष्टियों के विपरीत, जहां तत्काल पिछला अभिलेख अनुकरणीय प्रदर्शन दिखाता है, हाल के अतीत के ऐसे अभिलेख की अनदेखी करना और केवल पुरानी प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर कार्य करना, किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्त करना शक्ति के मनमाने प्रयोग का एक स्पष्ट उदाहरण होगा। **हालांकि, अगर पुराना अभिलेख किसी व्यक्ति की ईमानदारी से संबंधित है तो यह सरकारी कर्मचारी के समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को सही ठहराने के लिए पर्याप्त हो सकता है।**

(महत्व दिया गया)

प्यारे मोहन लाल (सुप्रा) में विचार दोहराया गया था। एकमात्र चेतावनी यह है कि पूरे अभिलेख को ध्यान में रखा जाना चाहिए और पदोन्नति के बाद भी पहले के अभिलेख को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

13. **पटना उच्च न्यायालय बनाम श्याम देव सिंह**¹⁰ में, यह न्यायालय एक ऐसे मामले से निपट रहा था जहां एक न्यायिक अधिकारी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया

¹⁰(2014) 4 एस सी सी 773

था और उसे 2 वर्ष की सेवा के लाभ से वंचित कर दिया गया था। इस न्यायालय ने इस प्रकार माना है:

"8. इस मुद्दे के महत्व को शायद ही हासिल किया जा सकता है। निरंतर उपयोगी सेवा के लिए उसकी क्षमता के बारे में एक राय बनाने के उद्देश्य से एक न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख का मूल्यांकन उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, जिसका स्पष्ट अर्थ है प्रशासनिक पक्ष पर पूर्ण न्यायालय। सभी उच्च न्यायालयों में ऐसा मूल्यांकन, प्रथमतः वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा किया जाता है। समिति के निर्णय को यह निर्णय लेने के लिए पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाता है कि समिति की सिफारिश को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। अंतिम निर्णय हमेशा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा मामले पर विस्तृत विचार से पहले होता है जो विचाराधीन न्यायिक अधिकारी के गुणों और विशेषताओं से परिचित होते हैं। वर्तमान मामले में भी यही हुआ है। जिस प्रक्रिया से अंततः निर्णय लिया जाता है, हमारे विचार में, एक सीमित न्यायिक समीक्षा की अनुमति होनी चाहिए और यह केवल एक दुर्लभ मामले में है जहां लिया गया निर्णय किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है या वही एक निष्कर्ष को दर्शाता है, जो इसके चेहरे पर, कायम नहीं रह सकता है कि न्यायिक समीक्षा की अनुमति होगी।

वाँश ऑफ सिद्धांत।

14. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य तर्कों में से एक यह है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं को विभिन्न उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए पदोन्नति से पहले उनका अभिलेख अपना स्टिंग खो देगा और इसका बहुत अधिक मूल्य नहीं है। **डी. रामास्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य**¹¹ मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है। जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया:

"4. कुछ महीने पहले अपीलकर्ता की पदोन्नति के सामने और उसके बाद अयोग्यता या अक्षमता का हल्का सा भी संकेत नहीं है, अपीलकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने के सरकार के आदेश को बनाए रखना असंभव है। तमिलनाडु राज्य के वकील ने तर्क दिया कि सरकार अपीलकर्ता के पूरे इतिहास को ध्यान में रखने की हकदार थी,

¹¹(1982) 1 एस सी सी 510

जिसमें उसका वह हिस्सा भी शामिल था जो उसकी पदोन्नति से पहले था। हम यह नहीं कहते कि एक सरकारी कर्मचारी के पिछले इतिहास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए, एक बार पदोन्नत होने के बाद। कभी-कभी, पिछली घटनाएं वर्तमान आचरण का आकलन करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन जब वर्तमान आचरण में पदोन्नति के ज्ञान पर कोई संदेह नहीं है, तो हम अतीत में अनावश्यक खुदाई के लिए कोई औचित्य नहीं देखते हैं।

15. *प्यारे मोहन लाल* (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें धोए गए सिद्धांत की अवधारणा से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने इस विषय पर पूरे मामले के कानून से निपटने के बाद निम्नानुसार आयोजित किया:

"24. उपरोक्त के मद्देनजर, कानून को संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यदि इस न्यायालय के दो या दो से अधिक निर्णयों के बीच कोई संघर्ष है, तो बड़ी पीठ के निर्णय का पालन किया जाना है। इसके अलावा, धुले हुए सिद्धांत का सार्वभौमिक अनुप्रयोग नहीं है। आगे पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारी के मामले पर विचार करते समय इसकी प्रासंगिकता हो सकती है, लेकिन ऐसे मामले में नहीं जहां कर्मचारी का मूल्यांकन समीक्षा प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है कि क्या वह सेवा में बनाए रखने के लिए फिट है या उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि समिति को उसके "संपूर्ण सेवा अभिलेख" को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयुक्तता का आकलन करना है।

xxx

xxx

xxx

29. कानून में प्राधिकरण को कर्मचारी के "संपूर्ण सेवा अभिलेख" पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जबकि यह आकलन करते समय कि क्या उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में उसे सूचित नहीं किया गया था और अधिकारी को उन प्रतिकूल प्रविष्टियों के बावजूद पहले पदोन्नत किया गया था। इसके अलावा, सुदूर अतीत में भी किसी अधिकारी की सत्यनिष्ठा के संबंध में एक भी प्रतिकूल प्रविष्टि अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए

पर्याप्त है। न्यायिक अधिकारी को समाज के अन्य अंगों से भिन्न मानते हुए उसके मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वह राज्य की एक भिन्न हैसियत से सेवा कर रहा है। न्यायिक अधिकारी के मामले पर माननीय मुख्य न्यायमूर्त द्वारा विधिवत गठित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति द्वारा विचार किया जाता है और तब समिति की प्रतिवेदन को पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाता है।

मामले पर विधिवत विचार-विमर्श करने के बाद पूर्ण न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है इसलिए, दिमाग का इस्तेमाल न करने या दुर्भावना से आरोप लगाने का शायद ही कोई मौका हो।

16. अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विषय पर कानून, विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों के मामले में संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:

(i) एक न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्देश देने वाला आदेश प्रकृति में दंडात्मक नहीं है;

(ii) किसी न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निदेश देने वाले आदेश का कोई सिविल परिणाम नहीं होता है;

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए न्यायिक अधिकारी के मामले पर विचार करते समय न्यायिक अधिकारी के संपूर्ण अभिलेख पर विचार किया जाना चाहिए, हालांकि बाद वाले और अधिक समकालीन अभिलेख को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए;

(iv) पदोन्नतियों का अर्थ यह नहीं है कि न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्णय करते समय पूर्व के प्रतिकूल रिकार्ड की जांच नहीं की जा सकती है;

(v) 'धोया गया' सिद्धांत न्यायिक अधिकारियों के मामले में विशेष रूप से सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में लागू नहीं होता है;

(vi) न्यायालयों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति सामान्यतः उच्च न्यायालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (समितियों) की सिफारिश पर निर्देशित की जाती है, अत्यधिक सावधानी और संयम के साथ न्यायिक पुनवलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यह पूर्वोक्त कानून के प्रकाश में है कि अब हम वर्तमान मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करेंगे।

17. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुवीक्षण समिति ने इस न्यायालय के आदेशों के बाद ही विस्तृत तर्क दिया है और न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे को देखते हुए, जब *दुर्भावना* का कोई आरोप नहीं है, हम इस तरह के आदेश को बनाए रखने के कारण देने से बचेंगे क्योंकि यह सजा की राशि नहीं है और प्रकृति में दंडात्मक नहीं है। हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा है कि उनके खिलाफ कोई सामग्री नहीं है, इसलिए हमारे पास अनुवीक्षण समिति द्वारा दिए गए कुछ कारणों का उल्लेख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

श्री अरुण कुमार गुप्ता का मामला

18. जहां तक श्री अरुण कुमार गुप्ता का संबंध है, उनके विरुद्ध दो बहुत गंभीर आरोप हैं। पहला यह कि जब वह रांची में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के उप निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, तब 10 से अधिक महिलाओं ने, जो सिविल सेवा परिवीक्षाधीन थीं, आरोप लगाया कि वह अपने व्याख्यान के दौरान अनुचित और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग कर रहे थे, अभद्र उदाहरणों का हवाला देते हुए और दोहरे अर्थ वाले शब्दों का उपयोग कर रहे थे, जिससे महिला अधिकारियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हमने उन शिकायतों का अवलोकन किया है जो उत्तर के साथ दर्ज की गई हैं और आम धारणा यह है कि श्री गुप्ता द्वारा अपने व्याख्यानों के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अत्यधिक कामुक थी।

19. एक और आरोप यह भी है कि उसने धोबी के सिर पर गर्म लोहा रखकर एक धोबी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई थी, जिसने कथित तौर पर अपने कपड़ों को ठीक से इस्त्री नहीं किया था। यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रधान जिला न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि पीड़ित ने घटना के तुरंत बाद व्यक्तिगत रूप से उनसे

संपर्क किया था और उन्होंने (प्रधान जिला न्यायाधीश) पाया कि पीड़ित को जलने की चोटें आई थीं और उन्होंने पीड़ित का इलाज कराया। यह सच है कि श्री अरुण कुमार गुप्ता को उत्तराधिकारी न्यायिक अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था, जिसके समक्ष शिकायतकर्ता ने किसी भी चोट से इनकार किया था, लेकिन हम यह गौर कर सकते हैं कि यह एक प्रारंभिक जांच है और उत्तराधिकारी प्रधान जिला न्यायाधीश ने अपने पूर्ववर्ती प्रधान जिला न्यायाधीश की जांच करने की भी परवाह नहीं की, जिसे न केवल धोबी द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया था, लेकिन जिसने खुद जलने की चोटों को गौर किया था और पीड़ित का इलाज करवाया था। इसलिए, हमारा विचार है कि जांच समिति सही थी कि पीड़ित पर अपनी शिकायत वापस लेने के लिए कुछ दबाव डाला गया होगा। ये घटनाएं वर्ष 2011-2012 की हैं और इन्हें बहुत पुरानी नहीं कहा जा सकता।

20. हमारे विचार में, उपरोक्त दो उदाहरण याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले का फैसला करने के लिए पर्याप्त हैं। हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि याचिकाकर्ता के लिए पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन ने आग्रह किया है कि अनुवीक्षण समिति ने केवल 1992-1993 से 2004-2005 तक प्रविष्टियों को लिया था और 2005-2006 से 2016-2017 तक प्रविष्टियों को नजरअंदाज कर दिया था। जैसा कि उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुनील कुमार द्वारा स्पष्ट किया गया है, सभी एसी आरएस अनुवीक्षण समिति के समक्ष थे लेकिन आदेश में केवल प्रतिकूल प्रविष्टियां टिप्पणी की गई हैं। जैसा कि यह हो सकता है, हमारा विचार है कि भले ही इन प्रतिकूल प्रविष्टियों को नजरअंदाज कर दिया जाए, याचिकाकर्ता को उपरोक्त कारणों से राहत नहीं दी जा सकती है।

श्री राज नंदन राय का मामला

21. जहां तक इस अधिकारी का संबंध है, हम पाते हैं कि कई मामलों में उसका रिकार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनकी प्रतिष्ठा और अखंडता पर 1996-1997, 1997-1998 और 2004-2005 के वर्षों में एक से अधिक बार संदेह किया गया है। उन्हें कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां दी गई हैं। वर्ष 2015-2016 में कानून और प्रक्रिया के बारे में उनका ज्ञान भी औसत पाया गया और बार के सदस्यों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं पाए गए। उनके

खिलाफ अवैध परितोषण के लिए जमानत देने के भी आरोप हैं और न्यायिक आयुक्त, रांची (जो प्रधान जिला न्यायाधीश के समकक्ष हैं) की प्रतिवेदन में इस आरोप में सार पाया गया है। अधिकारी ने आदेश में यह उल्लेख करते हुए जमानत दी थी कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 327 जमानती है जबकि अपराध गैर-जमानती है और न्यायिक अधिकारी की ईमानदारी के बारे में उसे 2012 में एक अलिखित चेतावनी जारी की गई थी

निष्कर्ष

22. जैसा कि ऊपर उद्धृत कानून से स्पष्ट है, सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रतिकूल प्रविष्टियां किसी भी स्तर पर अपना डंक नहीं खोती हैं। एक न्यायिक अधिकारी की सत्यनिष्ठा उच्च कोटि की होनी चाहिए और यहां तक कि एक भी विपथन की अनुमति नहीं है। जहां तक वर्तमान मामलों का संबंध है, जांच समिति द्वारा इस मामले पर दो अवसरों पर विचार किया गया है और जांच समिति की सिफारिशों को स्थायी समिति द्वारा दोनों अवसरों पर स्वीकार किया गया है। की गई कार्रवाई किसी एक अधिकारी या न्यायाधीश द्वारा नहीं की गई है, यह सामूहिक निर्णय है, पहले जांच समिति द्वारा और तत्पश्चात् स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

23. उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों, जो स्क्रीनिंग समिति और स्थायी समिति के सदस्य थे, ने एक सुविचारित और सुविचारित निर्णय लिया है। जब तक दुर्भावना के आरोप नहीं लगते हैं या तथ्य इतने स्पष्ट नहीं होते हैं कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय समर्थन योग्य नहीं है, तब तक यह अदालत न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी। ऐसे मामलों में न्यायिक पक्ष की अदालत को ऐसे सामूहिक निकायों के फैसले को रद्द करने से पहले संयम बरतना चाहिए जिसमें उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं। हमारी राय में ये उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त मामले नहीं हैं।

24. उपरोक्त के मद्देनजर, दोनों रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। कोई भी लंबित आवेदन (ओं) का निपटान किया जाएगा.

कल्पना के. त्रिपाठी

रिट याचिकाएं खारिज

यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।